बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

आर प्रज्ञाननंदा ने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पराजित किया

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रिलीज से पहले विवादों में बटवारा

Page-05

केरल में इ्रग्स केस पर सियासत तेज CPI(M) का दावा- आरोपी सतीसन की सोशल मीडिया टीम से जुड़ा

केरल में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। CPI(M) का दावा है कि कासरगोड में इ्रग्स के साथ पकड़े गए तीन लोगों में से एक, मुख्यमंत्री VD सतीसन की सोशल मीडिया टीम से जुड़ा था। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उस व्यक्ति का मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था। हाल ही में कासरगोड में PA अब्दुल सलाम, KH मुहम्मद हुसैन और PA अब्बास को गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस को एक कार में 130 ग्राम MDMA ले जाते हुए पाया गया। CPI(M) ने अब आरोप लगाया है कि हुसैन, सतीसन के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक, उनके सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल में उन्हें "टीम VD सतीसन/सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर" बताया गया है, जबकि उनके अकाउंट पर मौजूद पोस्ट में एक वीडियो भी है जिसमें मुख्यमंत्री उनके घर जाते हुए दिख रहे हैं, जब वे विपक्ष के नेता थे। CPI(M) के राज्य सचिव MV गोविंदन ने इन आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उनसे सफाई मांगी। गोविंदन ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को इ्रग तस्करी के मामले में गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुसैन, सतीसन से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स को मैनेज करते थे और कांग्रेस नेता के पोस्टर और वीडियो शेयर करने में शामिल थे। गोविंदन ने कहा कि मुख्यमंत्री VD सतीसन को इस बात का जवाब देना होगा कि उनका अपना ऑफ़िस कथित तौर पर इ्रग नेटवर्क का अड्डा कैसे बन गया।

CJP का 'जंतर-मंतर सीजन 2' का ऐलान

अभिजीत दिपके बोले- जल्द शुरू होगा नया आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को कहा कि 'जंतर-मंतर सीजन 2' जल्द शुरू होने वाला है। उनके इस बयान के बाद राजधानी दिल्ली समेत देशभर में CJP की आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।अभिजीत दिपके ने कहा कि सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर लगातार लोग उनसे पूछ रहे थे कि 'जंतर-मंतर सीजन 2' कब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।CJP का यह ऐलान पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के संदर्भ में आया है। उस दौरान परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुए थे। CJP ने इन प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और खुद को छात्रों तथा युवाओं की आवाज उठाने वाले दबाव समूह के तौर पर पेश किया था।पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने स्पष्ट किया कि 'जंतर-मंतर सीजन 2' का मतलब केवल दिल्ली में एक और प्रदर्शन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देशभर में संगठन की गतिविधियों और जनसंपर्क अभियान के बड़े चरण की शुरुआत का संकेत है।सौरव दास के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ जनता के स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है। CJP अब इन मुद्दों को समझने और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए देशव्यापी 'लिसनिंग टूर' शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन एक व्यापक अभियान चलाएगा और स्वतंत्रता दिवस के बाद शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।वहीं, अभिजीत दिपके ने दिल्ली में पार्टी के वॉलंटियर्स की बैठक के लिए जगह नहीं मिलने का भी दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई हॉल मालिकों ने बैठक के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और इसके पीछे 'ऊपर से दबाव' होने की बात कही।दिपके ने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में CJP के वॉलंटियर्स की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन संगठन को हॉल उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं मिला। उनके मुताबिक, कई लोगों ने निजी तौर पर यह कहा कि उन पर ऊपर से दबाव है, इसलिए वे पार्टी को जगह किराए पर नहीं दे सकते।दिपके ने इस कथित दबाव के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, उनके आरोपों पर बीजेपी की ओर से किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। अब CJP के 'जंतर-मंतर सीजन 2' के ऐलान के बाद देखना होगा कि संगठन अपने देशव्यापी अभियान को किस तरह आगे बढ़ाता है और शिक्षा के मुद्दे पर उसका अगला कदम क्या होता है।

महाराष्ट्र में मिलावटखोरों पर MCOCA की तैयारी योगेश कदम बोले- शरद पवार NDA में आएं तो स्वागत

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) राज्य मंत्री योगेश कदम ने मिलावटखोरी, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक घटनाक्रमों पर कई बड़े और महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। योगेश कदम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लेकर कहा कि ऐसे अपराधियों पर MCOCA लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि FDA मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खाने की चीजों में मिलावट करने वालों को चेतावनी देते हुए योगेश कदम बोले कि दूध, पनीर और एनालॉग पनीर में मिलावट करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि मिलावट करने वाले अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कदम ने बताया कि संभाजीनगर समेत राज्य के कई हिस्सों में FDA की कार्रवाई जारी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मिलावटखोर कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच के न निकल सकें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में में एनालॉग पनीर पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर बोलते हुए योगेश कदम ने NCP (शरद पवार गुट) के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में शरद पवार की पार्टी NDA के साथ आती है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें बढ़ी हैं। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता के आने से गठबंधन को मजबूती ही मिलेगी।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप सही

संसदीय समिति ने कैश मामले में जताई गंभीर आपत्ति

संसदीय जांच समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया है। समिति ने अपनी जांच में कहा कि उनके सरकारी आवास के परिसर में बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली, जिसका कोई स्पष्ट हिसाब-किताब सामने नहीं आया। पैनल ने यह भी माना कि घटना से जुड़े सबूतों को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया और जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं थे।समिति की जांच का केंद्र 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग की घटना थी। आग बुझाने के बाद परिसर के एक स्टोररूम में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद मामले ने गंभीर कानूनी और राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया था और जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संसदीय समिति गठित की गई।पैनल ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ तीन औपचारिक आरोपों की जांच की। समिति के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की समीक्षा के बाद तीनों आरोपों को सही पाया गया। हालांकि, रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि बरामद हुई नकदी आपराधिक कानून के तहत व्यक्तिगत रूप से जस्टिस वर्मा की ही थी।समिति ने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र वाले सरकारी आवास के परिसर में भारी मात्रा में ऐसी नकदी मिली, जिसके स्रोत, स्वामित्व और वहां रखे जाने की वजह को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि स्टोररूम में केवल कुछ नोट नहीं थे, बल्कि 500 रुपये के नोटों के बंडल और बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद थी।पैनल ने जस्टिस वर्मा की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि स्टोररूम पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर था। समिति के मुताबिक, संबंधित कमरा उनके आधिकारिक आवासीय परिसर का हिस्सा था और इस वजह से उसे पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर नहीं माना जा सकता।जांच समिति ने सबूतों को सुरक्षित रखने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए। समिति का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण घटना से जुड़े साक्ष्यों को संरक्षित करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा की ओर से नकदी की मौजूदगी और उससे जुड़े सवालों पर दिए गए जवाबों को भी पैनल ने टालमटोल वाला और असंतोषजनक बताया।

रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप

बिहार की राजनीति में हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदे गए डस्टबिन की कीमतों को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक काफी गरमा-गर्मी पैदा कर दी है। दरअसल रजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक यूट्यूबर की रिपोर्ट के आधार पर डस्टबिन घोटाले का आरोप लगाया है। यूट्यूबर ने बेगूसराय के रहने वाले व्यक्ति की तरफ से किए गए आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर बताया है कि सरकार ने 15490 रुपये में डस्टबिन खरीदा है। RTI से मिली क़ीमत की तुलना बाजार में मिलने वाले सामान्य डस्टबिन से RTI फ़ाइल करने वाले व्यक्ति ने की है। यूट्यूबर ने इसी तुलनात्मक चार्ट के आधार पर वीडियो बनाया है जिसे रोहिणी ने पोस्ट कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सरकार को घेरते हुए "डस्टबिन घोटाला" का गंभीर आरोप लगाया है।

FCRA संशोधन विधेयक

प्रियंका गांधी का विरोध, बोलीं- बिल वापस लिया जाए

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी FCRA संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिए।इसी बीच केंद्र सरकार ने विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा। सरकार के इस कदम के बाद अब विधेयक पर आगे की प्रक्रिया संयुक्त संसदीय समिति की जांच और रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी।लोकसभा की अतिरिक्त कार्यसूची में दी गई जानकारी के मुताबिक, विधेयक की जांच के लिए गठित

संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे। इनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। लोकसभा के 21 सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे।संयुक्त संसदीय समिति को विदेशी अंशदान से जुड़े प्रस्तावित बदलावों की विस्तार से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद के सामने पेश करनी होगी। प्रस्ताव में समिति की बैठकों के लिए कोरम भी तय किया गया है। इसके मुताबिक, बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। विधेयक को JPC के पास भेजे जाने के बावजूद विपक्ष ने इसके प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्ति कायम रखी है।

बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का क्या बचेगा? आजादी के दावे के बीच गहराता अस्तित्व का संकट

बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलगाववादी गतिविधियों और आजादी के दावों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक महत्व वाले इस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान की एकता, सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।

बलूचिस्तान के लोगों ने कल यानि 11 अगस्त को धूम धाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बलूचों ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है और देश के ज्यादातर हिस्से से कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का वजूद क्या बचेगा? इस सवाल का पहला उत्तर ही यही है कि करीब आधा पाकिस्तान ही एक झटके में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43.6 प्रतिशत हिस्सा बलूचिस्तान है यानी देश का लगभग आधा हिस्सा। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, कोयला और दूसरे खनिज भी भरपूर मात्रा में हैं। साथ ही इसकी तटरेखा और ग्वादर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व मिलता है। फिर भी यह प्रांत पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहां संसाधन तो बहुत हैं लेकिन इस बात को लेकर लगातार शिकायतें रहती हैं कि उन पर किसका नियंत्रण है, उनसे किसे फायदा होता है और वहां रहने वाले लोगों को कितना लाभ मिलता है। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहां बलोच, ब्राहुई, पश्तून और दूसरे समुदाय मिलकर ऐसी विविधता बनाते हैं जिसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता। लेकिन आज इनकी पहचान पर पाकिस्तानी सेना कहर बरपा रही है। विद्रोह, हमले, लोगों का जबरदस्ती गायब किया जाना और बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याओं के बाद पाकिस्तानी सेना से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद के लिए यह बात चिंता का विषय होनी चाहिए। क्योंकि जब गायब हुए पुरुषों के लिए न्याय की मांग करने वाली माताओं, बहनों और बेटियों की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है तो यह संकट सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता। यह वैधता का सवाल बन जाता है। फिर भौगोलिक स्थिति की बात भी है। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से लगती हैं जिससे पाकिस्तान दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के बीच एक अहम चौराहे पर स्थित हो जाता है। बलूचिस्तान के हटने से पाकिस्तान एक रणनीतिक इलाके, संसाधन, रणनीतिक गहराई और अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। लेकिन इससे भी गहरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान क्या बन गया है। कोई देश सिर्फ सीमाओं के दम पर नहीं टिक सकता। उसे अपने लोगों का भरोसा जीतना होता है। और पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो बलूचों के लिए एक देश नहीं बन पाया। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक बलूचिस्तान में लापता लोगों का मुद्दा एक नासूर बन चुका है। आवाज उठाने वाले युवाओं, छात्रों और पत्रकारों का गायब हो जाना वहां एक खौफनाक आम बात हो गई है। इसीलिए जब कोई देश अपने ही नागरिकों को 'दुश्मन' या 'दूसरे दर्जे का नागरिक' समझने लगे तो वह सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय आत्मा भी खोने लगता है। पाकिस्तान का निर्माण एक खास विचारधारा के तहत हुआ था लेकिन बलूचिस्तान के साथ उसका सुलूक यह साबित करता है कि वह अपने ही लोगों को एक सूत्र में पिरोने में नाकाम रहा है और इसीलिए कल जब स्वतंत्रता दिवस का दिन था तो बलूचों ने आजादी का जश्न मनाकर पूरे पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि जरा सोच कर देखो कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का वजूद क्या बचेगा।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी की

रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि रूसी जहाजों को जब्त करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ रूस जवाबी कदम उठाएगा। पुतिन ने साथ ही स्पष्ट किया कि रूस की यह कार्रवाई किसी एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं होगी। हम जहां भी आवश्यक समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्ती की घटनाओं पर सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि पश्चिमी देश रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन योजनाओं को अमल में लाया गया, तो हमें भी उसी तरह जवाब देना होगा। 'तास' की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि यह सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, जहां रूसी जहाजों को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां भी हम इसे आवश्यक और उचित समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। कहीं भी, यहां तक कि प्रशांत बेड़े (पैसिफिक फ्लीट) के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में भी। रूसी नौसैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने उनसे इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और पैसिफिक फ्लीट के कमांड को भी जानकारी दे दी गई है। इसलिए मैं इस मामले में उनके सुझावों का इंतजार करूंगा। न्यूज एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ ही वह अपने पड़ोसी और मित्र देशों के साथ आपसी सहमति वाले समाधान तलाशने के लिए भी तैयार है।

स्पाइसजेट की एक फ़्लाइट को टेक-ऑफ़ से पहले ही रोक दिया गया

केबिन के अंदर असहनीय गर्मी की शिकायत की

उत्तर भारत के 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

देशभर में मानसून एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के 12 राज्यों समेत कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। ऐसे में अगर आप 6 अगस्त को यात्रा की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर पढ़ लें।ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण उत्तर, पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। पूर्वी भारत में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जबकि हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमांचल क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय जिले, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब के कुछ हिस्से तथा पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली (6 अगस्त- भारी बारिश और आंधी का अलर्ट): राजधानी में पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ कई दौर की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

रूस-यूक्रेन निवेश विवाद में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने रूस के मध्यस्थ

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को रूस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह विवाद यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ओशचाडबैंक और रूस के बीच है। मामला रूस और यूक्रेन के बीच 1998 में हुई द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत शुरू हुआ है। ओशचाडबैंक ने रूस के खिलाफ यह दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण बैंक की संपत्तियों और कारोबार को भारी नुकसान हुआ। ओशचाडबैंक का कहना है कि उसे डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में मौजूद अपनी संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों का नुकसान उठाना पड़ा। बैंक इस नुकसान के लिए रूस से मुआवजे की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक का दावा सैकड़ों मिलियन डॉलर का है। बैंक ने जुलाई 2025 में रूस को इस विवाद के संबंध में औपचारिक नोटिस भेजा था। कथित तौर पर रूस की ओर से इसका जवाब नहीं मिलने के बाद ओशचाडबैंक ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस और ओशचाडबैंक के बीच इस मामले की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण बनाया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ को रूस ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। कोस्टा रिका की पूर्व व्यापार मंत्री और मध्यस्थ डायाला जिमेनेज न्यायाधिकरण की अध्यक्ष होंगी। उन्हें रूस और ओशचाडबैंक दोनों ने मिलकर चुना है। तीसरे मध्यस्थ के तौर पर यूनान के निवासी एवं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकौलाकिस को ओशचाडबैंक ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। इस तरह तीनों सदस्यों में एक-एक को रूस और ओशचाडबैंक ने चुना है, जबकि अध्यक्ष का चयन दोनों पक्षों की सहमति से हुआ है।जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम इससे पहले भी रूस से जुड़े दो निवेश विवादों में सामने आ चुका है। विंटरशॉल डी और उक्रेनगॉस से जुड़े मामलों में रूस ने उन्हें अपना मध्यस्थ बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था। इस मौजूदा मामले में खास बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने रूस की ओर से मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति स्वीकार की है।

कांगो में इबोला का कहर तेज, 3 महीने से कम समय में 2 हजार से ज्यादा मौतें

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला फैलने के आधिकारिक ऐलान के 3 महीने से भी कम वक्त में 2 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि इनमें से कम से कम 1 हजार मौतें बीते 3 सप्ताह में हुई हैं, क्योंकि यह Ebola वायरस तेजी से फैल रहा है। बीते मंगलवार तक कांगो के 5 प्रांतों में इबोला के कुल 4 हजार 381 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 हजार 11 मौतें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल अफ्रीकी देश कांगो में यह अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस का प्रकोप है। यह 2014 से 2016 के बीच वेस्ट अफ्रीका में फैले वायरस के कहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप है, जिसमें 11 हजार 310 लोगों की मौत हुई थी। गौरतलब है कि Ebola की महामारी के तेजी से फैलने की वजह से अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की तरफ से नियुक्त सीनियर इबोला कोऑर्डिनेटर, जूलियन हार्नीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Ebola से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए कहा: आज इबोला से मरने वालों की संख्या 2 हजार से अधिक हो गई है, जिनमें से आधी मौतें बीते 20 दिनों में हुई हैं। हम सभी राहतकर्मी, संगठन, सरकारें, डोनेट करने वाले और समुदाय को मिलकर और ज्यादा काम करना होगा, और यह काम आज ही से करना होगा, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और इबोला वायरस को रोका जा सके साथ ही, WHO ने X पर बताया कि उसने जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लोकल मैटरनिटी वार्ड को 20 बेड दान किए हैं। इसके अलावा, संगठन ने 100 हाइजीनिस्ट, 100 सर्विलांस और I P C अधिकारियों, 4 डीकंटैमिनेशन टीमों और 2 अंतिम संस्कार टीमों को ट्रेनिंग भी दी है। इसके साथ ही, WHO के अधिकारियों ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने के अपने संकल्प की बात दोहराई। फ्रंटलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया है कि कांगो के Lita में WHO की तरफ से बनाए गए इलाज केंद्र का विस्तार हो रहा है, जिससे इसकी क्षमता शुरुआती 40 बेड से दोगुनी 80 बेड हो जाएगी। इस प्रयास में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ UNICEF, ALIMA, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और MONUSCO जैसे ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स भी मदद कर रहे हैं। इससे पहले मई में खबर आई थी कि इबोला वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई थी।

संपादक की कलम से

संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों से देशहित में गंभीर बहस की उम्मीद की जाती है। लेकिन मौजूदा सत्र में जिस तरह लगातार हंगामा, नारेबाजी और कार्यवाही स्थगित होने की स्थिति बन रही है, वह संसदीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है।बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यह कहना कि जनता देख रही है कि चर्चा से कौन भाग रहा है, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आखिर कब होगी। सरकार के पास बहुमत है और उसके पास विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने और नीतियों की कमियों को सामने रखने का संवैधानिक अधिकार है। दोनों भूमिकाएं तभी सार्थक होंगी, जब सदन चलेगा।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार होने की बात सकारात्मक संकेत है। लेकिन केवल चर्चा की पेशकश या विपक्ष पर आरोप लगाने से गतिरोध खत्म नहीं होगा। सरकार को भी विपक्ष की चिंताओं को सुनने और जरूरी मुद्दों पर पर्याप्त समय देने की पहल करनी होगी। दूसरी ओर विपक्ष को भी विरोध का ऐसा तरीका चुनना चाहिए जिससे संसद की कार्यवाही पूरी तरह ठप न हो।संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है। कई बार विपक्ष ने विरोध के जरिए सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर किया है। लेकिन विरोध और व्यवधान के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। यदि हर मुद्दे का समाधान नारेबाजी और सदन की कार्यवाही रोकने में तलाशा जाएगा, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होगा।आज जरूरत सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ाने की नहीं, बल्कि संवाद का रास्ता खोलने की है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि संसद किसी एक दल की नहीं, बल्कि देश की जनता की संस्था है। सांसदों को मिले अधिकारों के साथ उनकी जिम्मेदारी भी जुड़ी है।संसद जितनी देर बाधित होगी, उतना ही नुकसान जनता के सवालों और लोकतांत्रिक बहस का होगा। इसलिए सत्ता पक्ष को उदारता और विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी होगी। लोकतंत्र में जीत केवल विधेयक पास कराने या सरकार को घेरने में नहीं, बल्कि सार्थक बहस के जरिए देश के सामने बेहतर रास्ता रखने में है। संसद चलेगी, तभी लोकतंत्र की आवाज मजबूत होगी।

परिसीमन पर तमिलनाडु में सियासी घमासान आधव अर्जुन बोले- दक्षिण का प्रतिनिधित्व कमजोर न हो

तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन ने आबादी के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन का विरोध करते हुए दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई है।उन्होंने कहा कि सीटों के पुनर्निर्धारण से उत्तर भारत का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ सकता है और तमिलनाडु की आवाज कमजोर हो सकती है।

तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से दक्षिणी राज्यों खासकर तमिलनाडु का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की राजनीति में उत्तर भारत का वर्चस्व और बढ़ेगा। आधव अर्जुन ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में दक्षिण भारत और तमिलनाडु से भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस बनाम भाजपा का मुद्दा नहीं है। यह राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने का सवाल है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में तमिलनाडु उत्तर भारतीय वर्चस्व के अधीन हो जाए। मंत्री ने दावा किया कि संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण केंद्र सरकार कई बार ऐसे फैसले लागू कर देती है, जिनका तमिलनाडु विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि आज 234 सदस्यों वाली विधानसभा में भी कभी-कभी एक आवाज नहीं सुनी जाती। ऐसी स्थिति तमिलनाडु के साथ संसद में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास 100 सांसद होते, तो क्या NEET, GST या CAA इसी तरह लागू किए जाते? समस्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व की है। आधव अर्जुन ने तमिलनाडु के सभी 39 सांसदों से परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट होकर संसद में अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में परिसीमन कानून आए, सभी सांसदों को मौजूदा स्थिति को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखने की मांग करनी चाहिए और इसके विरोध में मतदान करना चाहिए, न कि सदन से बाहर निकलना चाहिए। मंत्री ने परिसीमन के संभावित वित्तीय और राजनीतिक प्रभावों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु केंद्र को दिए गए प्रत्येक एक रुपये के बदले केवल 29 पैसे वापस प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़ाई जाती है, तब भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व असंतुलित हो सकता है। आधव अर्जुन ने कहा कि परिसीमन का आधार चाहे जो भी हो, कुल लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही रहनी चाहिए। दक्षिण भारत को भविष्य में फिर ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, जहां उसका राजनीतिक प्रभाव लगातार कम होता जाए। आधव अर्जुन के बयान पर बीजेपी विधायक भोजराजन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव को अनावश्यक बताते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ी है तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। गांव नगर पंचायतों में और कस्बे शहरों में बदल रहे हैं। ऐसे में परिसीमन की जरूरत है।

झारखंड छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का तीखा हमला

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से की है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी, जिन्ना से भी बदतर नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना का दूसरा जन्म राहुल गांधी जी के तौर पर हुआ है। झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "वे CBI जांच क्यों नहीं चाहते? मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बड़े अधिकारी के घर से पकड़ा गया था। उन्हें पता है कि अगर जांच हुई, तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी आएगा। यही वजह है कि यह सब हो रहा है। उन्हें (कांग्रेस को) झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वे छात्रों के हित में खड़े हैं। वरना, ऐसा लगेगा कि वे सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "जहां भी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होता है, राहुल गांधी वहां नजर आते हैं। वह जिन्ना से भी बदतर नेता हैं।" भाजपा सांसद ने इसी बयान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, "जिन्ना की दूसरी पैदाइश राहुल गांधी जी के रूप में हो गई है।" झारखंड में नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन बुधवार को 19वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर पारदर्शिता, कई परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों की समिति से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों ने कई लोगों के घायल होने का दावा किया, जबकि रांची पुलिस के मुताबिक झड़प में उसके 14 जवान घायल हुए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान कई जिलों में सड़कें जाम रहीं, बाजार बंद रहे और शैक्षणिक संस्थानों पर भी असर पड़ा। बीजेपी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

संसद में हंगामे पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला बोले- जनता देख रही है कौन चर्चा से भाग रहा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही में व्यवधान को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जान-बूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है और सरकार की ओर से चर्चा के लिए तैयार रहने के बावजूद अहम मुद्दों पर बहस से बच रहा है।नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि संसद में विपक्ष की लगातार बाधा उसकी 'अराजक मानसिकता' को उजागर करती है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और अब यह भी समझ रही है कि चर्चा से वास्तव में कौन भाग रहा है।उन्होंने विपक्षी दलों पर संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद का उद्देश्य देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना और समाधान तलाशना है। ऐसे में लगातार नारेबाजी, हंगामा और कार्यवाही रोकने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह अपनी बात सदन के भीतर रखे और बहस के जरिए सरकार से जवाब मांगे।नितिन नवीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब संसद के मौजूदा सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। हंगामे के कारण कई बार सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है, जिससे विधायी कामकाज भी प्रभावित हुआ है।इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के साथ बातचीत और संसदीय बहस के लिए सरकार की तत्परता जताई थी। शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि सरकार सभी प्रकार की संसदीय चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बातचीत के बजाय विरोध-प्रदर्शन के जरिए अव्यवस्था पैदा कर रहा है। उन्होंने विपक्ष से लोकसभा अध्यक्ष को चर्चा के लिए पत्र देने की अपील भी की थी।शाह ने यह भी कहा था कि सरकार बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि विपक्ष को अपनी मांगें और सवाल संसदीय प्रक्रिया के तहत उठाने चाहिए।वहीं विपक्षी दलों का तर्क है कि जिन मुद्दों को वे जनहित से जुड़ा और महत्वपूर्ण मानते हैं, उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि विरोध और दबाव के जरिए ही सरकार को गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए मजबूर किया जा सकता है।इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए सहमति बनाते हैं या आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रहती है।

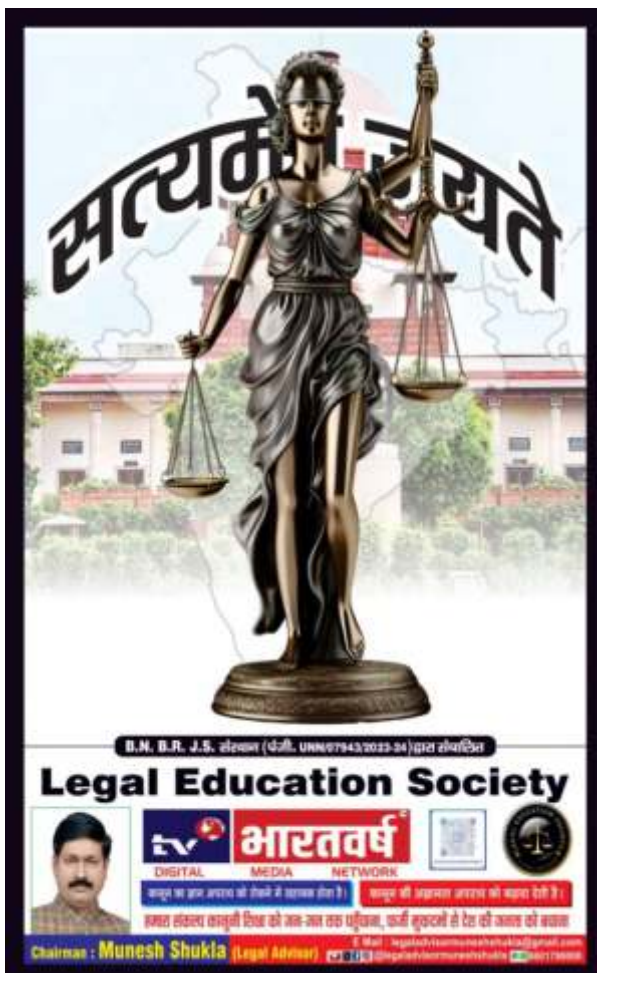

बिहार की जानू कुमारी को मिली 96 लाख की GKS स्कॉलरशिप दक्षिण कोरिया में करेंगी मास्टर्स की पढ़ाई

विदेश में हायर एजुकेशन हासिल करने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत जरूरी होती है। कई सारे देशों में भारतीय स्टूडेंट्स को लाखों रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन इन्हें हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। स्कॉलरशिप के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है और सीटें कम होती हैं। ऐसे में अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी ही उपलब्धि जानू कुमारी ने हासिल की है, जो अब फुली-फंडेड स्कॉलरशिप पर साउथ कोरिया पढ़ने जा रही हैं। जानू कुमारी का सिलेक्शन प्रतिष्ठित 2026 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप (GKS) के लिए हुआ है। इस स्कॉलरशिप के तहत वह दक्षिण कोरिया की सन मून यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करेंगी। भारतीय छात्रा की इस उपलब्धि से उनके परिजन काफी ज्यादा खुश हैं। स्कॉलरशिप की अवधि 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 तक है।

स्कॉलरशिप के जरिए भारतीय छात्रा को साउथ कोरिया आने-जाने के लिए फ्लाइट टिकट भी मिल रहा है।

सन मून यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करने के लिए कोई ट्यूशन फीस भी नहीं देनी है।

स्कॉलरशिप के जरिए रहने-खाने के लिए स्टाइपेंड भी दी जा रही है।

भारतीय छात्रा को कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेना है, क्योंकि वो भी स्कॉलरशिप के जरिए कवर किया गया है।

स्कॉलरशिप की टोटल वैल्यू 96 लाख रुपये है, जो 3 सालों के दौरान दी जाएगी। भारतीय छात्रा जानू ने बताया कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप साउथ कोरिया के शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन (NIIED) द्वारा प्रदान की जाती है। हर साल इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और भारत से सीमित संख्या में स्टूडेंट्स का सेलेक्शन होता है। हर साल 2400 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें से 1900 स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के लिए रिजर्व है। वैसे तो मास्टर्स 2 साल की होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को 1 साल तक कोरियाई भाषा की पढ़ाई करवाई जाती है। परिजनों के अनुसार, जानू बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। भारतीय छात्रा पिछले करीब 3 साल से ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए लगातार तैयारी कर रही थी। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और इसे हासिल कर लिया। जानू कुमारी बिहार की रहने वाली हैं और उन्होंने भागलपुर स्थित शारदा झुनझुनवाला महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है।

एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई को लेकर परेशान?

हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में बेहतर करियर के लिए पहले नीट यूजी और फिर नीट पीजी में बैठते हैं। इस साल नीट पीजी 30 अगस्त 2026 को होने वाला है। लेकिन कई राज्यों के एडमिशन ब्रोशर्स ने पहले ही मेडिकल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक साल पहले दिए फैसले के बाद भी कई राज्य अलग-अलग नियम लागू कर रहे हैं। इसे नीट पीजी सीट पर छात्रों को समान अवसर नहीं मिलने का डर सता रहा है। दरअसल, मेडिकल एडमिशन का यह मामला राज्यों में अलग-अलग पात्रता और शर्तों का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले राज्य कोटे के तहत पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए निवास या डोमिसाइल (मूल निवासी होने) को आधार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि NEET-PG उम्मीदवारों के माता-पिता का कहना है कि राज्यों में एडमिशन के नियम अभी भी अलग-अलग हैं। इससे एक ही नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के बावजूद छात्रों को समान मौके नहीं मिल पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में निवास-आधारित प्राथमिकता की परमिशन नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि एडमिशन NEET-PG स्कोर के आधार पर होने चाहिए और केवल सीमित संस्थागत प्राथमिकता की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी छात्र को किसी खास मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए प्राथमिकता मिल सकती है, न कि इसलिए कि वह किसी राज्य का निवासी या डोमिसाइल है।

18 साल के करियर को अलविदा कहने के बाद रहाणे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पैनल में नजर आएंगे

डेविड मिलर का बड़ा लक्ष्य, 2027 वर्ल्ड कप जीतकर करना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कब करेंगे, इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मिलर आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर करियर का समापन करना चाहते हैं। यह वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में ही खेला जाएगा। वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है; साल 2023 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर ने 'जियोस्टार' से कहा "हां, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं। मैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर ट्रॉफी के साथ समापन करना पसंद करूंगा। इसलिए, मेरे लिए उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना एक लक्ष्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और मैं निश्चित रूप से, अभी से लेकर तब तक, उस टीम में जगह बनाने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जाहिर है, अपने फैंस के सामने और उस

जगह पर खेलना बहुत खास होगा जहां मैंने इतने वर्षों तक खेला है। इसलिए, उस टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा।" मिलर ने 'द हंड्रेड 2026' में सदर्न ब्रेव के लिए आठ मुकाबलों में 166 रन बनाए, उन्होंने अपने लंबे करियर और शानदार तरीके से मैच खत्म करने की कला के बारे में कहा, "शायद यह बात कि मैंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके और मैच खत्म करके अपना करियर बनाया है; यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। इसमें महारत हासिल करने में काफी समय लगता है। मैं अभी भी हर समय सीख रहा हूं, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र में मेरा करियर लंबा रहा है, और मैंने विशेष रूप से लक्ष्य का पीछा करते हुए खेलने का बहुत आनंद लिया है।"

आर प्रज्ञाननंदा ने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पराजित किया

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर के मैच में जावोखिर सिंदारोव के डिफेंस को ध्वस्त करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। दूसरे दौर के स्टार प्रज्ञाननंदा रहे जिन्होंने रानी के सामने वाले प्यादे से शुरुआत करके धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत की और आखिर में जीत हासिल करने में सफल रहे। सिंदारोव ने काले मोहरों से खेलते हुए बाजी ड्रॉ कराने को प्राथमिकता दी लेकिन वह प्रज्ञाननंदा की प्रतिबद्धता का अनुमान नहीं लगा पाए। इसका भारतीय खिलाड़ी को फायदा मिला जिन्होंने 95 चाल में जीत हासिल की। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी सिंदारोव का इस साल के आखिर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के खिलाफ विश्व खिताब के लिए मुकाबला होगा। इस जीत से प्रज्ञाननंदा के 1.5 अंक हो गए हैं। उन्होंने पहले दौर की बाजी ड्रॉ खेली थी। इस बीच पहले दौर में जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ ड्रॉ खेला। दूसरे दौर में प्रज्ञाननंदा सहित चार खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। अमेरिका के लेवोन अरोनियन ने जर्मनी के विन्सेंट कीमर को, अमेरिका के ही वेस्ली सो ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फोरेस्ट को और फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव ने अमेरिका के सावियन सैमुअल को हराया।

टेस्ट से पहले बांग्लादेश को राहत, लिटन दास पूरी तरह फिट

बांग्लादेश की टीम अभी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जिसमें उनको पहला मुकाबला 13 अगस्त से डार्विन के मैदान पर मेजबान टीम के खिलाफ खेलना है। बांग्लादेश को इस टेस्ट सीरीज का आगाज होने से पहले अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने से समस्या से जूझना पड़ा है, लेकिन अब उन्हें एक अच्छी खबर मिली है जिसमें उनके अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास पहला मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हो गए हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने डार्विन टेस्ट मैच के एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटन दास को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं और पहले मैच में चयन के लिए उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में होने वाले टेस्ट मुकाबले को लेकर नजमुल हुसैन शांतो ने लिटन दास को लेकर कहा कि उनके आने से हमारी बैटिंग मजबूत होती है। वह लगातार अच्छा खेलते हैं। हमें उम्मीद है कि टेस्ट मैच में हमारी बैटिंग यूनिट अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं शांतो ने प्लेइंग 11 को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पिच अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि हम अपने सामान्य कॉम्बिनेशन के साथ ही जा सकते हैं, जैसे दो स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज। लेकिन हालात को देखते हुए कल सुबह पिच को हमें फिर से देखने का मौका मिलेगा और फिर हम हालात के हिसाब से फैसला करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश की टीम साल 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंची है, ऐसे में उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है।डार्विन टेस्ट के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का अगले एक साल तक काफी व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है जिसमें उनके लिए अपने अहम प्लेयर्स का वर्कलोड भी मैनेज करना आसान नहीं रहने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान

मुकाबले से एक दिन पहले ही कर दिया है, जिसमें टीम में जोश हेजलवुड की वापसी हुई है, एशेज 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्कॉट बोलैंड को पहले की प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना गया है।जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

कुछ सेकंड का Video कर देगा हैरान

मौत सामने थी, बच्चों के लिए ढाल बन गई मां

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी सांसे थम जाएंगी. वीडियो में एक मां अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद उनकी ढाल बनकर रेलवे ट्रैक के बेहद करीब लेटी नजर आ रही है. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजरती है. कुछ सेकेंड का यह पूरा घटनाक्रम इतना खतरनाक है कि वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक के पास फंसी हुई है. सामने से ट्रेन तेजी से गुजर रही है. खतरा भांपते ही महिला अपने बच्चों को अपने शरीर से ढक लेती है और उन्हें कसकर अपने पास पकड़ लेती है. ट्रेन इतनी करीब से गुजरती है

कि महिला और बच्चों के बीच से निकलने वाली जगह बेहद कम दिखाई देती है. मां खुद खतरा उठाते हुए बच्चों के ऊपर लेटी रहती है, ताकि ट्रेन की चपेट में आने से उन्हें बचाया जा सके. कुछ पल तक वहां ऐसा माहौल रहता है कि देखने वाले भी डर जाते हैं.

मां की हिम्मत देखकर लोग रह गए हैरान

वीडियो देखने वाले कई लोग महिला के हौसले की तारीफ कर रहे हैं. बच्चों के लिए मां का खुद को खतरे में डालना लोगों को भावुक भी कर रहा है. कुछ ही सेकेंड में महिला ने जिस तरह बच्चों को अपने शरीर से ढक लिया, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए मां के साहस को सलाम कर रहे हैं. वहीं, यह घटना यह भी याद दिलाती है कि रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन के आसपास थोड़ी सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

सोशल मीडिया पर हो रही कंपनी की तारीफ

'वीकेंड पर काम नहीं होगा, चाहे क्लाइंट चले जाएं'

आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहां कई कंपनियों में देर रात तक काम करना और वीकेंड पर भी लैपटॉप खोलना आम बात हो गई है, वहीं एक बिजनेसवुमन ने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया. उन्होंने साफ कह दिया कि शाम 6 बजे के बाद उनकी कंपनी में कोई काम नहीं होगा और वीकेंड पर कर्मचारियों को ऑफिस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा. इस फैसले की वजह से कुछ क्लाइंट्स ने उनकी कंपनी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपने नियम नहीं बदले. अब उनकी लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. मुंबई में जन्मीं सारा शैम चौथी

पीढ़ी की बिजनेसवुमन हैं. उनका परिवार करीब 130 साल पुराने एंटीक कारोबार से जुड़ा है. बाद में उन्होंने दुबई की लग्जरी इंटीरियर डिजाइन कंपनी Jea की सह-स्थापना की. हाल ही में उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर एक पोस्ट लिखी, जिसने हजारों लोगों का ध्यान खींचा.

थिएटर में चले लात-घूंसे!

फिल्म का स्पॉइलर सुनते ही मचा बवाल

नई स्पाइडर-मैन फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कथित तौर पर एक दर्शक ने फिल्म के अहम सीन बताने शुरू कर दिए. वायरल वीडियो में इसके बाद थिएटर के अंदर बहस और धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है.

अगर आप भी फिल्म देखते समय कोई स्पॉइलर सुनना पसंद नहीं करते, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. नई स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक दर्शक ने कथित तौर पर फिल्म के अहम सीन पहले ही बताने शुरू कर दिए.

इसके बाद थिएटर में ऐसा हंगामा हुआ कि मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक, चार दोस्त नई

स्पाइडर-मैन फिल्म देखने पहुंचे थे. उनके बगल में बैठा एक युवक पहले ही यह फिल्म देख चुका था और अपनी महिला मित्र को फिल्म के आगे आने वाले सीन और बड़े ट्विस्ट बताने लगा.

पोस्ट में दावा किया गया है कि युवक बार-बार स्पॉइलर देता रहा. इससे आसपास बैठे दूसरे दर्शकों का फिल्म देखने का मजा खराब होने लगा. कुछ देर बाद चारों दोस्तों ने युवक का विरोध किया और उसे ऐसा करने से मना किया. बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में थिएटर के अंदर कई लोग एक-दूसरे से बहस करते और हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि फिल्म का स्पॉइलर बताना गलत है, क्योंकि इससे पहली बार फिल्म देखने वाले लोगों का पूरा अनुभव खराब हो जाता है. वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में हिंसा सही नहीं मानी जा सकती. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लोगों से अपील की कि अगर वे कोई फिल्म पहले देख चुके हैं, तो थिएटर के अंदर उसके अहम सीन, क्लाइमैक्स या पोस्ट-क्रेडिट सीन के बारे में दूसरों को न बताएं.

जनरल डिब्बे में पंखा साथ लेकर चढ़ गया शख्स

भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लेकिन समय-समय पर रेलवे से जुड़े ऐसे वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, जो यात्रियों की लापरवाही और सार्वजनिक संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर सवाल खड़े करते हैं. कभी सीट को लेकर मारपीट, कभी सीट का कवर काटने की घटना, तो कभी ट्रेन में आग लगाने जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आ चुके हैं.

रिलीज से पहले विवादों में फंसी 'बंटवारा'

आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर फैन्स में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की स्टारकास्ट इसका जमकर प्रमोशन कर रही है. फिल्म प्रमोशन के दौरान लीड हीरो सनी देओल ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है.

यानी फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. आइए जानते हैं कि सनी ने ऐसा क्या कहा, जिसके लिए इतना कोहराम मचा हुआ है. सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन में बिजी हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक पहले

एक्टर विवादों में घिर गए हैं. फिल्म प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर ने सनी देओल से पूछा कि वो पड़ोसी देश को किस नजरिए से देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया- पहले दोनों देश एक ही थे. जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, भारत मां है और पाकिस्तान भारत से ही निकला है, इसलिए वो मौसी बन गया. हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

आयुष्मान योजना में सख्ती

184 निजी अस्पतालों की मान्यता खत्म, कैशलेस इलाज पर रोक

उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर 184 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से डी-इम्पैनल किया गया है। फायर एनओसी और बायोमेडिकल वेस्ट जैसे मानकों में कमी मिलने पर कार्रवाई हुई। मानक पूरे करने पर दोबारा इम्पैनलमेंट संभव है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले 184 निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-इम्पैनल कर दिया गया है। अब इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी। अस्पतालों के खिलाफ यह कार्रवाई नए और सख्त मानकों के आधार पर किए गए सत्यापन के बाद की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी संबद्ध अस्पतालों की व्यवस्थाओं और जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई थी। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता से संबंधित मानकों को और सख्त किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में योजना से जुड़े अस्पतालों के दस्तावेज और व्यवस्थाओं का विस्तृत सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान अस्पतालों से फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई अनिवार्य मानकों को पूरा करने और उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अस्पतालों को निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए मार्च से लगातार अवसर और जरूरी सूचनाएं दी जा रही थीं। इसके बावजूद कई अस्पताल तय समय सीमा में आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर फायर एनओसी जैसे मानक सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा से जुड़े हैं। इनमें कमी पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई और 184 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया। डी-इम्पैनल किए गए 184 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी इन अस्पतालों में योजना के कार्ड के आधार पर आयुष्मान भारत के तहत उपचार का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। यह कार्रवाई अस्पतालों की संख्या कम करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में वही अस्पताल जुड़े रहेंगे जो निर्धारित सुरक्षा, गुणवत्ता और अन्य जरूरी मानकों का पालन करेंगे। सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि योजना के लाभार्थियों को ऐसे अस्पतालों में इलाज मिले, जहां मरीजों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता से समझौता न हो। डी-इम्पैनल किए गए अस्पतालों के लिए योजना से दोबारा जुड़ने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। अगर संबंधित अस्पताल भविष्य में सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा कर लेते हैं और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं, तो वे नियमों के तहत फिर से इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्पताल की व्यवस्थाओं और दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन करेगा। मानक पूरे होने पर नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

लखनऊ में फुटपाथ दुकानदार का पूरा फूड काउंटर चोरी

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में जान्हवी इन्क्लेव चौराहे से एक फुटपाथ दुकानदार का फूड काउंटर चोरी हो गया। चोर काउंटर के साथ कुर्सी-मेज, 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर और अन्य सामान भी उठा ले गए। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब उसने डीसीपी से शिकायत करने की बात कही है। धर्मावितखेड़ा निवासी योगेश मिश्रा जान्हवी इन्क्लेव चौराहे के पास 'पंडित जी दाल फरे' नाम से लाल-पीले रंग का फूड काउंटर लगाते थे। इसी कमाई से उनके परिवार का गुजारा चलता है। योगेश के अनुसार, यह चोरी 9 और 10 अगस्त की मध्यरात्रि को हुई, जब चोर पूरा फूड काउंटर सामान सहित ले गए। सुबह चोरी का पता चलने पर योगेश मिश्रा ने स्थानीय चौकी और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय केवल जांच का आश्वासन दिया और उन्हें वापस भेज दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित परेशान है। योगेश मिश्रा का कहना है कि इस चोरी से न केवल उनके सामान का नुकसान हुआ है, बल्कि उनके परिवार की रोजी-रोटी भी प्रभावित हुई है। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई के लिए लगातार चक्कर लगवाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने स्पष्ट किया है कि यदि मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वह डीसीपी से लिखित शिकायत कर न्याय की मांग करेंगे।

रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज की बड़ी तैयारी, 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलेंगी

रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। 26 से 31 अगस्त तक परिवहन निगम की अधिकतम बसें सड़कों पर उतरेंगी। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को यात्रियों की मांग के अनुसार अतिरिक्त बसें संचालित करने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री ने खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ, कानपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। रक्षाबंधन के दौरान बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त रोशनी और पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों को बसों के संचालन की जानकारी देने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। अधिकारियों को बस अड्डों पर लगातार मौजूद रहकर भीड़ और बसों की उपलब्धता पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 26 से 31 अगस्त तक बस संचालन से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर पहले से तैयार किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस दौरान अवकाश और साप्ताहिक विश्राम स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अनुबंधित बसों को भी पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। छह दिनों में 1800 किमी बस संचालन की पात्रता पूरी करने वाले चालक-परिचालकों को 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संविदा चालक-परिचालकों को 1800 किमी से अधिक संचालन पर अतिरिक्त दूरी के लिए 55 पैसे प्रति किमी की दर से प्रोत्साहन मिलेगा। डिपो और क्षेत्रीय कार्यशाला में छहों दिन उपस्थित रहने वाले तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपए एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

लखनऊ में 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा, हजारों युवा होंगे शामिल

लखनऊ में तिरंगे के महत्व और देशभक्ति का संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ युवा शक्ति की ओर से आयोजित यात्रा का रूट 1090 चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक तय किया गया है। यात्रा सुबह 11 बजे शुरू होगी। यात्रा को लेकर बुधवार को गोमतीनगर स्थित किसान बाजार के मीटिंग पॉइंट पर बैठक हुई। आयोजकों ने बताया कि इसमें हजारों छात्र और युवा शामिल होंगे। युवा दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। आयोजकों के मुताबिक, यात्रा का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी और खासकर जेन-जी युवाओं को तिरंगे का महत्व बताना है। इसके जरिए युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रप्रेम और सकारात्मक सोच का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। लखनऊ युवा शक्ति ने युवाओं से अपने मित्रों और साथियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की है। आयोजकों का कहना है कि यह एक जागरूकता अभियान है, जिसका मकसद युवाओं को जोड़ना और उनमें देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह किसी राजनीतिक दल या नेता का कार्यक्रम नहीं है। इसी वजह से यात्रा में राजनेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसे पूरी तरह तिरंगा यात्रा और युवा जागरूकता अभियान के रूप में आयोजित किया जा रहा है। बैठक में लव सिंह, श्रीराम त्रिपाठी, राज शेख सिंह, रितेश सिंह और प्रशांत चतुर्वेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

लखनऊ में 16 अगस्त को हरियाली तीज का भव्य आयोजन

लखनऊ 16 अगस्त को हरियाली तीज के मौके पर एक खास आयोजन का गवाह बनेगा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित अटल प्रेक्षागृह में 2100 महिलाएं एक साथ हरियाली तीज के गीतों पर सामूहिक प्रस्तुति देंगी। आयोजकों का दावा है कि इसके जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाएं हरे परिधान, चूड़ियों और मेहंदी से सजकर सावन के गीतों पर प्रस्तुति देंगी। पारंपरिक झूलों और लोकधुनों के बीच होने वाली यह सामूहिक प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगी। रिकॉर्ड प्रयास की निगरानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि प्रीति सिंह लखनऊ पहुंचेंगी। आयोजन की जिम्मेदारी शिवी शिल्पग्राम की अध्यक्ष और महिला उद्यमी पुनीता भटनागर संभाल रही हैं। शिवि शिल्पग्राम, भार्गव काम्प्लेक्स, जय नारायण लेन, हुसैनगंज में बुधवार कों हुई प्रेस वार्ता में पुनीता भटनागर ने बताया कि सावन सनातन संस्कृति में उत्सव और उल्लास का महीना है। हरियाली तीज, कजरी, झूले और सावन के गीत हमारी पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा हैं। इसी विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है।

राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 4350 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान 30 सितंबर 2026 तक हर हाल में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने बताया कि एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पुरुष संवर्ग में 2200 और महिला संवर्ग में 1800 शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है। पुरुष शिक्षकों की पिछले 15 वर्षों से जबकि महिला शिक्षकों की 10 वर्षों से पदोन्नति नहीं हो पाई है। वहीं प्रवक्ता से राजपत्रित अधिकारी पद पर पिछले दो वर्षों से 350 शिक्षकों की प्रोन्नति भी अटकी हुई है। इस लंबे इंतजार के कारण शिक्षकों में काफी रोष था। नियमों के मुताबिक एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पांच साल की सेवा पूरी करने पर प्रोन्नति का प्रावधान है। प्रवक्ता पद पर 12 साल की सेवा के बाद इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य या हाईस्कूल में प्राचार्य बनाया जाता है। प्रवक्ता पद पर सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को तीन साल की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य या प्राचार्य का मौका मिलता है। दो वर्ष की सेवा के बाद इंटर कॉलेज में प्राचार्य या बीएसए पद पर भी प्रोन्नति संभव है। शिक्षक संघ ने आकांक्षी जिलों में तैनात शिक्षकों के तबादले, तदर्थ राजकीय शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद तदर्थ सेवा का लाभ दिए जाने सहित कई अन्य मांगें भी निदेशक के समक्ष रखीं। निदेशक के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल टाल दिया है।

उन्नाव में पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने किया पिछड़ेपन का अध्ययन सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर जुटाई जानकारी

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने बुधवार दोपहर दो बजे उन्नाव के विकास भवन सभागार में बैठक की। इस दौरान आयोग ने जिले में पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोग के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों से पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के संबंध में सुझाव और जानकारी एकत्र की। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़ापन केवल एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि इसका अध्ययन सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सहित कई स्तरों पर किया जा रहा है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में विशेष रूप से राजनीतिक पिछड़ेपन की स्थिति को समझना और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी से जुड़ी वास्तविक जानकारी जुटाना था। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोग को बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की सीमित उपलब्धता के साथ-साथ शिक्षा का अभाव भी पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगारपरक यानी जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। आयोग के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि उन्नाव प्रदेश का 21वां जिला है, जहां टीम ने पहुंचकर लोगों और जनप्रतिनिधियों से जानकारी जुटाई है। आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों का भ्रमण कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। विभिन्न जिलों में बैठकें आयोजित कर लोगों के सुझाव और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों और प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। ओबीसी आरक्षण के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि अब तक जिन जिलों का भ्रमण किया गया है,

शुक्लागंज में देशभक्ति के जोश के साथ निकली तिरंगा यात्रा

उन्नाव के शुक्लागंज में बुधवार शाम देशभक्ति के जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा प्रकाश ज्वाला देवी बालिका इंटर कॉलेज से शाम करीब 7:15 बजे शुरू हुई। कॉलेज के प्रबंधक भरत त्रिवेदी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक, भाजपा नेता-कार्यकर्ता और समाजसेवी शामिल हुए। यह आयोजन शासन की मंशा के अनुरूप 7 से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे तिरंगा यात्रा पर्व का हिस्सा था। यात्रा में सदर विधायक पंकज गुप्ता भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे छात्र-छात्राएं और स्थानीय लोग देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के जयघोष से राजधानी मार्ग सहित आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। यह यात्रा राजधानी मार्ग से होते हुए विभिन्न स्थानों से गुजरी। रास्ते में तिरंगा यात्रा को देखने के लिए जगह-जगह स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने यात्रा का उत्साह बढ़ाया और राष्ट्रभक्ति के इस आयोजन की सराहना की। यात्रा में शामिल बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और पुलिसकर्मी यात्रा के साथ चलते हुए मार्ग पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। पुलिस की निगरानी में यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी। इस यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शुक्लागंज में देशभक्ति का माहौल और भी उत्साहपूर्ण बना दिया।

औरास में बिजली कटौती और ट्रिपिंग से लोग परेशान

उन्नाव के औरास क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों को राहत दिलाने के लिए बुधवार को बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंकर लाल गौतम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंपकर औरास पावर हाउस को जालामऊ (रहीमाबाद) स्थित 132 केवी पावर हाउस से जोड़ने की मांग की। यह पत्र अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पंचम, हसनगंज की अनुपस्थिति में उपखंड अधिकारी हसनगंज एसपी वर्मा को सौंपा गया। वर्तमान में औरास पावर हाउस को मियागंज स्थित 33 केवी पावर हाउस से बिजली आपूर्ति मिलती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मियागंज से औरास की अधिक दूरी होने के कारण 33 केवी लाइन में आए दिन ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन की समस्या होती है। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकारी और व्यावसायिक संस्थानों पर भी पड़ रहा है। बिजली संकट का असर औरास विकासखंड, नगर पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक और विद्यालयों समेत कई संस्थानों पर पड़ रहा है। क्षेत्र की करीब 2.5 लाख से अधिक आबादी बिजली कटौती से प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। लगातार बिजली गुल रहने से नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शंकर लाल गौतम ने पत्र में बताया कि जालामऊ (रहीमाबाद) स्थित 132 केवी पावर हाउस औरास से करीब 10 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि औरास पावर हाउस को जालामऊ से जोड़ दिया जाए तो लंबी दूरी की 33 केवी लाइन पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने विभाग से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच ग्रामीणों ने मियागंज के एसडीओ धर्मेंद्र कुमार पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीओ का सीयूजी नंबर अक्सर बंद रहता है, जिससे बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान में दिक्कत होती है। ग्रामीणों के मुताबिक, हाल ही में क्षेत्र में करीब 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। लगातार बिजली कटौती और अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाने के कारण लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बिजली व्यवस्था में सुधार कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।

गंगाघाट में खुलेआम गांजा बिक्री का वीडियो वायरल पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में खुलेआम गांजा बिक्री का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को सामने आए वीडियो में एक व्यक्ति के गांजा बेचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के कई इलाकों में लंबे समय से गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधि की पुष्टि होती है तो यह पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल लोगों के साथ ही इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की जांच की मांग की है। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी अवैध कारोबार को कथित संरक्षण देने और 'महीनवारी' के रूप में रकम लेने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से वीडियो और इन आरोपों को लेकर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर गांजा की बिक्री होती दिखाई दे रही है। वीडियो गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, वीडियो कब और कहां बनाया गया, इसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान क्या है और उसमें वास्तव में गांजा ही बेचा जा रहा है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगाघाट क्षेत्र के कुछ स्थानों पर लंबे समय से गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से नशे का कारोबार करने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं।

उन्नाव रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बुधवार दोपहर उन्नाव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन भवन के निर्माण, फाउंडेशन और कॉलम के चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 90 मीटर लंबे भवन का निर्माण किया जा रहा है। डीआरएम के अनुसार, भवन के लगभग 40 मीटर हिस्से में फाउंडेशन स्तर तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कॉलम लगाने का काम जारी है। इस हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद शेष लगभग 50 मीटर हिस्से पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी न हो। रेलवे की प्राथमिकता है कि स्टेशन के विकास कार्य को अगले वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को लगातार निगरानी और तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक से जुड़ी एक प्रस्तावित परियोजना को लेकर भी सवाल किया गया। बताया गया कि इस परियोजना का सर्वे पूर्व सांसद अन्नू टंडन के कार्यकाल में वर्ष 2012 में कराया गया था। इस पर डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि उन्हें परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेनी होगी।

उन्नाव के नेहरूबाग इंडस्ट्रियल एरिया में एंटी नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी

उन्नाव के नेहरूबाग इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार दोपहर एंटी नारकोटिक्स विभाग की टीम ने दो औद्योगिक इकाइयों पर छापेमारी की। ओम फार्मा और लुमेक कंपनी में नशीले पदार्थों से संबंधित सामग्री के उत्पादन की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। बुधवार दोपहर करीब दो बजे एंटी नारकोटिक्स विभाग की आठ सदस्यीय टीम ने दोनों कंपनियों में जांच शुरू की। टीम ने कंपनी परिसर में उत्पादन प्रक्रिया, स्टॉक, कच्चे माल और तैयार सामग्री से संबंधित दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की।

उन्नाव के नेहरूबाग इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार दोपहर एंटी नारकोटिक्स विभाग की टीम ने दो औद्योगिक इकाइयों पर छापेमारी की। ओम फार्मा और लुमेक कंपनी में नशीले पदार्थों से संबंधित सामग्री के उत्पादन की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। बुधवार दोपहर करीब दो बजे एंटी नारकोटिक्स विभाग की आठ सदस्यीय टीम ने दोनों कंपनियों में जांच शुरू की। टीम ने कंपनी परिसर में उत्पादन प्रक्रिया, स्टॉक, कच्चे माल और तैयार सामग्री से संबंधित दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की।

12 साल पुराने चुनावी केस में कुमार विश्वास को समन

27 अगस्त को कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

2014 के अमेठी लोकसभा चुनाव से जुड़ा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का करीब 12 साल पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कुमार विश्वास समेत अन्य आरोपियों को समन जारी करते हुए 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।

कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास से जुड़े करीब 12 साल पुराने चुनावी मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कुमार विश्वास समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।यह मामला उस समय का है, जब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। 2014 का अमेठी चुनाव काफी हाई-प्रोफाइल रहा था, क्योंकि यहां कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान कुमार विश्वास और उनके सहयोगियों की गतिविधियां भी राजनीतिक चर्चा में रही थीं।इसी चुनावी दौर में अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इसके बाद मामला विशेष एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है।इस मामले में कुमार विश्वास के अलावा आम आदमी पार्टी के तत्कालीन नेता सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र के आधार पर अदालत में मामले की कार्यवाही आगे बढ़ती रही। अब एक बार फिर अदालत ने आरोपियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने संबंधित आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए समन जारी किया। अदालत ने सभी आरोपियों को 27 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं। इस तारीख को मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही होगी और अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड तथा पक्षकारों की स्थिति के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है।हालांकि, इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत की ओर से समन जारी किया जाना किसी आरोपी के दोषी साबित होने के बराबर नहीं है। समन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्धि अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के बाद ही हो सकती है। इसलिए फिलहाल कुमार विश्वास और अन्य आरोपियों के खिलाफ केवल आरोपों और लंबित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही स्थिति देखी जा रही है।कुमार विश्वास के लिए यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 का अमेठी चुनाव उनके राजनीतिक करियर के महत्वपूर्ण चुनावों में शामिल रहा। उस समय आम आदमी पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को लेकर कई विवाद भी सामने आए थे।करीब 12 साल पुराने इस मामले के दोबारा सुर्खियों में आने के बाद अब 27 अगस्त की सुनवाई पर सबकी नजर है। यह देखना अहम होगा कि अदालत आगे मामले की सुनवाई किस दिशा में बढ़ाती है और आरोपियों की ओर से इस मामले में क्या कानूनी पक्ष रखा जाता है।

नोएडा एयरपोर्ट में बारिश से जलभराव का वीडियो वायरल

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में मंगलवार को बारिश के दौरान जलभराव का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हवाई अड्डा प्रबंधन ने कहा कि 30 मिनट के भीतर परिसर से पानी निकाल दिया गया और इससे विमानों के संचालन में कोई व्यवधान नहीं आया। सोशल मीडिया पर मंगलवार को प्रसारित वीडियो में हवाई अड्डे के टर्मिनल से निकलकर पार्किंग और टैक्सी स्टैंड तक जाने वाले भूमिगत मार्ग में जलभराव दिखाई दे रहा है। वीडियो में हवाई अड्डे के कर्मचारी पानी निकालने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खराब मौसम के कारण मंगलवार को धर्मशाला जाने वाली एक उड़ान भी रद्द कर दी गई। इस संबंध में हवाई अड्डे के जनसंपर्क विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, "बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी भर गया था, लेकिन हमारी टीम ने 30 मिनट के भीतर स्थिति सामान्य कर दी। इससे उड़ानों के संचालन या हवाई अड्डे के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।" गौतमबुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में विकसित किया जा रहा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में से एक है।

बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ पुलिस ने नवजात और दूधमुंहे बच्चों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। वहीं दो अन्य महिला आरोपी फरार हैं। पुलिस ने अपहृत तीन माह के मासूम को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में ऐनुल पुत्र कबीरुद्दीन, नौशाद पुत्र रशीद, नागेंद्र उर्फ सुक्का पुत्र बर्दी प्रसाद, नसीम पुत्र वकील, आबिद पुत्र केशू, श्रीमती सुमिया पत्नी रामकुमार और रुखसार पत्नी नौशाद शामिल हैं। जबकि सितारा पत्नी सहजाद और मोसिना पत्नी नफीस, निवासी कांधला, जनपद शामली अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 11 अगस्त को टीला मोड़ के करन गेट निवासी फुरकान ने अपने तीन माह के बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 12 अगस्त को कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ कर अपहृत मासूम को सकुशल बरामद कर लिया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे योजनाबद्ध तरीके से नवजात और दूधमुंहे बच्चों का अपहरण कर उन्हें निःसंतान दंपतियों को मोटी रकम लेकर बेचते थे। गिरोह की महिलाएं अस्पतालों और नवजात बच्चों वाले परिवारों की जानकारी जुटाती थीं। बच्चों की तस्वीरें व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सौदा तय किया जाता था।

शामली एनकाउंटर में एक लाख का इनामी फुरकान ढेर, पुलिस से मुठभेड़ में मार गिराया

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर एक्शन यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी है। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट से दुकानदारों को ध्वस्तीकरण को लेकर सीधी राहत तो नहीं मिली है। हालांकि, कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों के मामले में राज्य सरकार को नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें पुनर्वास के पहलू पर भी विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। आदेश के बाद अब बाजार को उजाड़ने के बजाय लैंडयूज परिवर्तन और नियमन के विकल्प पर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारी नेता संजीव मित्तल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों के संबंध में राज्य सरकार को नीति बनाने के निर्देश दिए। व्यापारियों का कहना है कि आदेश में सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण पर कोई रोक या सीधी राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अनधिकृत कॉलोनियों और दशकों पुराने मकानों की तोड़फोड़ से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कई जगह 30-40 साल पुरानी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से सरकारें टैक्स वसूलती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन देती हैं और नियमितीकरण का भरोसा भी देती हैं। इसके बावजूद वर्षों बाद अचानक इन बस्तियों को अवैध बताकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है।